म्यांमार की एक गुफा में भगवान बुद्ध की 9000 मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ तो सैंकड़ों साल पुरानी हैं। असल में यहाँ भक्तों ने भगवान बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए मूर्तियाँ रखी हैं। पिंडाया क्षेत्र अपनी लाइम स्टोन गुफाओं के लिए विख्यात है। इन्हीं में से एक है उपरोक्त श्वे यू मिन केव (गोल्डन केव)। मूर्तियों में कोई एल्बैस्टर (सिलखड़ी) से बनी है, कोई सागवान की लकड़ी या मार्बल से, कोई पत्थर या सीमेंट से तो कोई कांसे से। गुफा के दरवाजे पर है श्वे यू मिन पैगोडा। इस मठ के प्रार्थना कक्ष, अर्थात् ताज़ोंगा का निर्माण बौद्ध संत यू खांती ने किया था, जिसने मैन्डले हिल में भी कई धार्मिक स्मारक बनाए हैं। गुफा में भगवान बुद्ध की दो मूर्तियां ऐसी हैं जिनसे पसीना निकलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार किसी कारण से सिर्फ इन दो मूर्तियों पर ही पानी नजर आता है, और श्रद्धालुओं में इनका पसीना पोंछने की होड़ लगी रहती है। गुफा के 490 फुट लम्बे पैदल मार्ग के अंत में एक साइन पोस्ट के नीचे से लोग काली मिट्टी ले जाते हैं, यह जगह है ब्लैक क्ले हिलॉक। पिंडाया क्षेत्र की यही जगह ऐसी है जहाँ की मिट्टी काली है। लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसका इस्तेमाल बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करते हैं। गुफा में, छत से पानी टपकने के कारण चूने के कई स्तंभ, स्टलैग्माइट, बन गए हैं, जिन पर प्रहार करने से घंटे की ध्वनि निकलती है। पिंडाया गुफा के नामकरण की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं एक बार सात राजकुमारियाँ इस गुफा में आराम कर रही थीं कि तभी एक दैत्याकार मकड़ी ने दरवाजे को जाल से ढक दिया। राजकुमारियाँ मदद के लिए चिल्लाने लगीं तो उनकी आवाज वहां पास ही मौजूद एक राजकुमार ने सुन ली। इनमें से सबसे बड़ी व बुद्धिमान राजकुमारी ने कहा कि अगर राजकुमार ने उनकी मदद की तो सबसे छोटी व सबसे सुंदर राजकुमारी का विवाह उससे कर देंगे। राजकुमार ने तीर चलाकर मकड़ी को मार दिया, फिर वह चिल्लाया "पिंगु-या", अर्थात् मकड़ी मर गई। गौरतलब है कि म्यांमार में मकड़ी को पिंगु कहते हैं। इस कारण ही गुफा का नाम पिंगुया पड़ गया, बाद में इसे ही पिंडाया कहा जाने लगा।

गहलोत सरकार सुन नहीं रही इसलिए प्रियंका गांधी से मिलने यू.पी.पहुंचे राजस्थान के बेरोजगार युवा

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि, हमने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरु कर दी है

लखनऊ/ नई दिल्ली, 29 नवम्बर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कई दिनों से हड़ताल, शर्टलैस आंदोलन, मंत्रियों को गुलाब भेंट करने और भूख हड़ताल पर जाने के बाद अब राजस्थान के बेरोजगार युवकों ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। यह युवक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि, राजस्थान की गहलोत सरकार उनकी नहीं सुन रही है।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (आर.बी.ई.एम.) के बैनर तले आयोजित इस धरना का उद्देश्य राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारों की मांगों को पूरा कराना है। इनकी प्रमुख मांग सरकारी नौकरियों में नियुक्ति है। इसके लिए भर्ती परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए रिक्तियों की संख्या में वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती कानून तैयार करने की भी मांग कर रहे हैं।

धरने में शामिल होने पहुंचे आर.बी.ई.एम. के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि, हमने लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर धरने के बाद अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हम पिछले 47 दिनों से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश में 20 लाख नौकरियां देगी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।

- **उपेन यादव ने कहा कि, यू.पी. में कांग्रेस ने सरकार बनने पर 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, इससे पहले राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे को पूरी तरह से भूल गई है।**
- **उपेन यादव ने कहा कि, हम पिछले 47 दिनों से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं।**

इससे पहले आरबीईएम ने कहा था कि वह प्रियंका गांधी समेत अपने नेताओं की रैलियों में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का विरोध करेगी। उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद वे बेरोजगार युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय उत्तर प्रदेश के लोगों से बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। पहले पार्टी को राजस्थान में किए गए अपने वादों को पूरा करना चाहिए।

मुख्यमंत्री गहलोत के नवनियुक्त सलाहकार विधायक दानिश अबरार 23 नवंबर को प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और बातचीत की।

हालांकि, सहमति नहीं बनने पर प्रदर्शनकारी 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए और लखनऊ पहुंचकर उन्होंने यू.पी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया।

बिना बहस के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने कहा कि विपक्ष इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करता आया है और सरकार अब इसके लिए तैयार है तो बहस की जरुरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती, इसलिए वह शीतकालीन सत्र की अधिक इच्छुक नहीं है।

मोदी सरकार के नये भारत के लोकतंत्र का नमूना: उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि, संसद सत्र के पहले ही दिन बिना चर्चा के कृषि कानूनों की वापसी को हर कोई एक "नमूना" ही

श्रीनगर, 29 नवंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कृषि कानून वापस लेने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि संसद में बिना चर्चा कराये कृषि कानूनों को वापस लेने 'नये भारत के नये लोकतंत्र का नमूना' है।

उल्लेखनीय है कि 25 दिनों तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा कराए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया।

उमर ने कहा कि, संसद सत्र जारी रहने के दौरान लोकसभा में बिना चर्चा कराये कृषि कानूनों को रद्द किया जाना 'नये भारत के नये लोकतंत्र का नमूना' है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिना चर्चा के प्रस्ताव पास तथा बिना चर्चा के कानून रद्द। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी तीनों कानूनों को सरकार द्वारा संसद में वापस लेने को किसान और मजदूरों की जीत बताया है लेकिन कहा कि बिना चर्चा कराए ये तीनों कानून वापस लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि संसद में चर्चा से उसे डर लगता है।

- **उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि, अभी 25 दिन सत्र और चलेगा तो फिर सरकार को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी।**
- **राहुल गांधी ने भी कहा है कि, केन्द्र सरकार को संसद में चर्चा कराये जाने से डर लगता है, कहीं उनकी पोल -पट्टी ना खुल जाये।**

गांधी ने यहां संसद भवन में संवाददाताओं से कहा कि वह जानना चाहते हैं कि सरकार ने जब कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लिये तो इन पर चर्चा कराने से उसे किस बात का डर है। उनका कहना था कि सरकार जानती है कि उसने गलत काम किया है, इसलिए वह इस कानून को लेकर संसद में चर्चा कराने से भयभीत थी और उसने चर्चा नहीं कराने का रास्ता चुनकर इन कानूनों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि सरकार ने किसानों की ताकत के सामने झुककर कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लेने का फैसला लिया है लेकिन उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती थी ताकि यह भी पता चलता कि इस कानून को लाने के पीछे कौन सी ताकत थी।

वे तीन, चार पूंजीपति कौन हैं जो इन कानूनों के माध्यम से किसान की मेहनत पर हाथ मारने के लिए इस कानून के पीछे सख्ती से खड़ी थी। गांधी ने कहा कि इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगी थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का लोगों से माफी मांगने से स्पष्ट है कि उन्होंने गलती मान ली है कि सात सौ किसानों की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं इसलिए उन्हें अब किसानों को मुआवजा देना चाहिए।

सैन्ट्रल विस्टा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा कि यदि राज्यों ने प्रदूषण कम करने के लिए केन्द्र के एयर क्वालिटी कमीशन के दिशा-निर्देशों को पूर्णतया लागू नहीं किया तो उसे एक टास्क फोर्स के गठन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सी.जे.आई. ने मौखिक टिप्पणी की कि "यदि राज्य कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन को बाध्य होना पड़ेगा।

बैंच, जिसमें जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे, ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को भी निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के आदेश की अनुपालना के लिए शपथ-पत्र पेश करें।

बैंच ने कहा कि "हम प्रत्येक राज्य से यह पूछेंगे कि उन्होंने दिशा निर्देशों पर क्या क्रियान्विती की है, अन्यथा हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन को बाध्य होना पड़ेगा।

उन पर क्रियान्विती करनी ही होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो टास्क फोर्स का गठन ही एकमात्र रास्ता है। बैंच ने टिप्पणी की कि "शीर्ष अदालत ने इस पर जोर दिया था कि निर्देश जारी किए जा चुके हैं और प्रशासन को उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हकीकत में इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है।"

कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर भी कांग्रेस छोड़ेंगी

सांसद परनीत कौर ने अपने ट्विटर अकाउन्ट की डी.पी. से कांग्रेस शब्द हटाया

चंडीगढ़, 29 नवम्बर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर ने कांग्रेस छोड़ सकती हैं। परनीत कौर ने अपने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपन ट्विटर अकाउंट की डिसप्ले पिक्चर (डीपी) से कांग्रेस शब्द हटाते हुए कैप्टन फॉर 2022 लिख दिया है। परनीत कौर द्वारा ऐसा करना एक तरह पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का इनडायरेक्ट तरीके से जवाब देना भी माना जा रहा है।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने पिछले दिनों परनीत कौर को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब देने को कहा था। हरीश चौधरी ने परनीत कौर पर कांग्रेस विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भी परनीत कौर ने चुप्पी साध रखी थी और कांग्रेस में बने रहने या फिर इसे छोड़ने को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। इस दौरान वह पटियाला के पार्षदों की बैठक से लेकर कई जगह नजर आ चुकी है। इस दौरान पार्षदों ने कैप्टन के पक्ष में नारेबाजी की थी। इसके बाद पटियाला के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू के खिलाफ पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव संबंधी मामले में भी परनीत कौर ने राज्य सरकार की समर्थक पार्षदों के खेमे की खिलाफत की। परनीत कौर की इन गतिविधियों के चलते पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीती 24 नवंबर को उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि स्पष्ट करें कि वह मीडिया में ऐसे संकेत क्यों दे रही हैं कि वह अपने पति के साथ हैं। अब परनीत कौर द्वारा अपने ट्वीवीटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द हटाकर कैप्टन फार 2022 लिखकर सांसद द्वारा एक तरह से हरीश चौधरी द्वारा जारी नोटिस का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देना माना जा रहा है।

- **पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने पिछले दिनों परनीत कौर को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब देने को कहा था। हरीश चौधरी ने परनीत कौर पर कांग्रेस विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था।**
- **परनीत कौर द्वारा ऐसा करना एक तरह से हरीश चौधरी द्वारा उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस का इनडायरैक्ट जवाब भी माना जा रहा है।**

यू-टर्न से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतिम दिन की घटनाओं से संबंधित है, जब विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया था, सदन के वैल में चले गये थे, मेजों पर खड़े हो गए थे तथा सिक्योरिटी स्टाफ एवं मार्शलों के साथ उनकी धक्कामुक्की भी हो गई थी।

यह निलम्बन धारा 56 के तहत था लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि निलम्बन अगले सत्र तक नहीं पहुँचाया जा सकता। निलम्बन उसी दिन तक ही किया जाना चाहिये था, जिस दिन सत्र समाप्त हो रहा था।

यह भी कहा जा रहा है कि किन्हें निलंबित किया जाये तथा किन्हें छोड़ा जाये-इसका चयन सरकार ने सोच विचार कर किया है। उदाहरणार्थ, आप सांसद संजय सिंह, जो मेज पर नाचे थे, छोड़ दिये गये हैं। प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया?

जाहिर है कि सरकार विरोध के स्वर को तथा कृषि कानूनों की वापसी की प्रतिक्रिया को खामोश कर देना चाहती थी क्योंकि प्रधानमंत्री इन कानूनों की जबरदस्त तारीफ करते हुये, कह रहे थे कि यह भारत में अब तक का सबसे अच्छा काम है तथा ये कानून कृषि क्षेत्र में किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये "यू टर्न" से बड़ी अप्रसन्नता है, क्योंकि सरकार के हर व्यक्ति से यह कहा गया था था कि वह चर्चा के बिना पारित हुये इन विधेयकों का हर तरह से बचाव करे, इनके पक्ष में ही बोले। ये विधेयक जिस तरह बिना चर्चा कराये पारित हुये थे, ठीक उसी तरह चर्चा कराये बिना ही आज वापस ले लिये गये। विपक्षी नेताओं ने निलम्बन की भर्त्सना की है तथा इस मुद्दे को रणनीति का रूप देने के लिये, कल विपक्ष की मीटिंग होगी। वे राज्यसभा के सभापति से कहेंगे कि निलम्बन वापस लिया जाये तथा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विपक्षी सम्पूर्ण विपक्ष का आव्हान करेंगी कि पूरे सत्र के लिये राज्यसभा का बहिष्कार किया जाये। क्या लोकसभा में ऐसी ही कार्यवाही होगी, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित है कि इस निलम्बन के कारण संसद की गाड़ी पटरी से उतर जायेगी, क्योंकि विपक्ष इस पर उग्र प्रतिक्रिया देगा तथा वह हर संभव हथियार को काम में लेते हुये, इसका प्रतिकार करेंगे।

ट्विटर के सी.ई.ओ.जैक डॉर्सी ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया

न्यूयॉर्क, 29 नवम्बर। ट्विटर के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सी.ई.ओ.) जैक डोर्सी ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डोर्सी के बाद अब पराग अग्रवाल को ट्विटर को नया सी.ई.ओ. नियुक्त किया गया है। डोर्सी ने कंपनी के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि, कंपनी को-फाउंडर और सी.ई.ओ. तक की भूमिका निभाने के बाद लगभग 16 साल के बाद मैंने फैसला किया है कि आखिरकार मेरे लिए जाने का समय आ गया है।

ट्विटर ने सोमवार को घोषणा की कि कंपनी के मुख्य तकनीकी अधिकारी पराग अग्रवाल जैक डोर्सी की जगह लेंगे।

- **ट्विटर ने पराग अग्रवाल को कंपनी का नया सी.ई.ओ. नियुक्त किया है।**

सोशल मीडिया कंपनी ने बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से पराग अग्रवाल की सी.ई.ओ. और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। पराग अग्रवाल पिछले एक दशक से ट्विटर से जुड़े हुए हैं। एक विशेष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर जॉइन किया था और फिर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने। ट्विटर से पहले पराग अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट, याहू और ए.टी. एंड टी. लैब्स के साथ काम कर चुके हैं।

राजस्थान का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फूल भेंट करना। इनके अलावा, यह ग्रुप भूख-हड़ताल भी कर चुका है। अन्य चीजों के अन्तर्गत इस ग्रुप की माँग है कि ज्यादा नौकरियाँ निकाली जायें तथा ऐसा कानून बनाया जाये कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने के जिम्मेदार लोगों की गैर-जमानती गिरफ्तारी की जा सके।

तमिलनाडु में बाढ़ से अब तक 59 लोगों की मौत

चेन्नई, 29 नवंबर (वार्ता)। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी। राज्य में अभी तक बारिश और बाढ़ से कुल 59 लोगों ने जान गंवाई है।

राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन ने बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से कहा कि कुड्डालोर जिले से मौत की खबर सामने आयी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत से अभी तक बारिश और बाढ़ से 59 लोगों की मौत हुयी है और मृतकों के परिजनों को सहायता के रूप में 2.36 करोड़ रुपये की राहत राशि दी गयी है। रामचंद्रन ने कहा कि 13 घायलों को 55900 रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी गयी है। जानकारी के अनुसार, राज्यभर में अभी तक 5600 मुर्गे और 209 मवेशियों की मौत हुयी है और 1074 झोपड़ियां और 189 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये और 65 झोपड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं।

- **सोमवार को वर्षा जनित हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है।**

उन्होंने कहा कि 2783 मवेशियों की मौत के लिये मुआवजे के रूप में 2.84 करोड़ रुपये दिये गये हैं और 24810 क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिये 10.17 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिये सरकार त्वरित कदम उठा रही है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित करीब 15000 से अधिक लोगों को तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, नागपट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई, पेरम्बलुर, अरियालुर, रानीपेट, थुतुकुडी, रामनाथपुरम, त्रिची, तिरुपट्टूर, तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर जिलों के 182 राहत शिविरों में रखा गया था।

चेन्नई में 1503 लोगों को 13 राहत शिविरों में रखा गया था, जहां उन्हें भोजन और दवा मुहैया करायी गयी। मुख्यमंत्री एम. के स्टालिन चेंगलपेट और कांचीपुरम जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों और शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों में जाकर लोगों को राहत सामग्री प्रदान की।

भाजपा ने कैसे त्रिपुरा में सूपड़ा साफ किया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भूमिका की निभाने की बड़ी व्याकुलता से तलाश कर रही थीं, ने अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए त्रिपुरा को लक्ष्य बनाया था।

ममता की मौजूदगी सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं और वर्ष 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों में वे स्वयं को संयुक्त विपक्ष के चेहरे के रूप में देखना चाहती हैं। कथित चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उनके सपनों को पंख को पर दिए हैं।

दुर्भाग्य से उनके पंख औंधे मुंह आकर गिरे और चुनावी जीत के बाद वे फिर स्वयं को प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के रूप में पेश करने की उम्मीद कर रही हैं।

कभी-कभी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का भ्रम होता आया है। उन्होंने अपने विश्वस्त प्रशंसक डेरेक ओ'ब्रायन के जरिए यह विचार भी प्रस्तुत करवाया कि बदलाव के लिए "एक बंगाली को प्रधानमंत्री होना चाहिए।"

लेकिन इसे फलीभूत करने के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्शाने की जरूरत है। उनकी पार्टी सिर्फ एक स्थानीय पार्टी है। एक राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें कम से कम कुछ अन्य राज्यों में उपस्थिति की जरूरत है। उन्होंने अपने प्रचंड अहं, यानी की प्रशांत किशोर के साथ विचार-विमर्श कर एक रणनीति बनाई थी, जिसमें उन्होंने सोचा कि त्रिपुरा एक सॉफ्ट टार्गेट है।

ममता का मानना था कि बंगालियों की उनके प्रति सतत निष्ठा को देखते हुए वे पश्चिम बंगाल के बाहर हर कहीं बंगालियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिपुरा के बंगाली उन्हें सत्ता में लाने के लिए बड़ी संख्या में वोट देंगे।

ममता बनर्जी अपनी पार्टी के पक्ष में लिखने के लिए बंगाल से सौ से अधिक पत्रकारों को साथ लेकर गई गई क्योंकि बंगाल में भी ऐसा ही कर रहे हैं। त्रिपुरा ने उनके विरूद्ध राज्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर उलझा दिया।

मुख्यमंत्री विप्लब देव भी तृणमूल कार्यकर्ताओं को अपने राज्य से बाहर खदेड़ने और उनकी गतिविधियों को अवरूद्ध करने में सक्रिय रहे हैं। शिकायतों से कम ही फायदा हुआ।

वास्तव में, विप्लब देब ने वैसे ही पैंतरे अपनाएं जैसे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनाए थे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वैसा ही सुलूक किया गया, जैसा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ किया गया। त्रिपुरा भाजपा ने इस संदर्भ में केन्द्रीय नेतृत्व के दिशा-निर्देशों की अनदेखी तक की।

त्रिपुरा नगर पालिका चुनाव भाजपा के लिए कुछ सबक लेकर आए हैं। पार्टी यहां इतनी सीटें जीती हैं जितनी उसने कहीं भी नहीं जीती।

तृणमूल कांग्रेस ने नगर पालिका चुनावों में सीटें जीतने को लेकर एक मजबूत प्रयास किया था, लेकिन अंत में उसे एक ही सीट मिल सकी।

औंधे मुंह गिरी तृणमूल ने चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा के आरोप लगाए हैं।

उसने यह भी दावा किया है कि पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूर्व राज्य में अपना खाता खोल लिया है।

उसका मानना था कि स्थानीय पार्टी होने के कारण उसे प्रचण्ड विजय मिल सकती है क्योंकि उसे पूरी छूट मिलती है तथा वह चुनाव सुधार निर्णीत पड़ौसी पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय नेतृत्व का भारी नेतृत्व कुछ विपरीत प्रतिक्रिया ही उत्पन्न कर सका।

त्रिपुरा में भाजपा का प्रदर्शन अन्य राज्यों के चुनावों के लिए निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। हौंसले को अब ऊंची उड़ान भरनी चाहिए।

राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिसकर्मी करोना पॉजिटिव

देहरादून, 29 नवम्बर (वार्ता)। उत्तराखंड के दो दिवसीय भ्रमण पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा व्यवस्था में नियुक्त राज्य पुलिस के गढ़वाल परिक्षेत्र के सात कार्मिकों में करोना संक्रमण होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले सेना के तीन जवानों में भी करोना का संक्रमण मिला था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति के ऋषिकेश गंगा तट पर आरती और उनके वहीं रात्रि विश्राम के कारण गढ़वाल परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसलिये 250 कार्मिकों का कोविड-19 का परीक्षण किया गया। इनमें से सात के करोना संक्रमित होने की रिपोर्ट रविवार को मिली।

दोनों सदनों ने पांच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सितम्बर 2020 में बने तीन विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के लिये पेश किया गया था। लोकसभा अपरान्ह 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

यह विधेयक लोकसभा में पूर्वान्ह काल में ही पारित हो गया था तथा इसी प्रकार से राज्यसभा में यह अपरान्ह काल में पारित हो गया। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुये कहा कि इस विधेयक पर चर्चा की कोई जरुरत ही नहीं है क्योंकि सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल- दोनों ही पक्ष कृषि कानूनों को वापस लिये जाने से सहमत हैं।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान मरने वाले 700 किसानों का मुद्दा उठाया।

उन्होंने सरकार का मखौल उड़ाते हुये कहा कि उसे इन कानूनों को वापस लेने की अक्ल सवा साल बाद, अब जाकर आई है और भी इसलिये कि उसने हाल ही में हुये उपचुनावों में माहौल देख लिया था तथा सरकार को डर था कि इन कानूनों के चलते, एन.डी.ए. पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हार जायेगा।

उप सभापति हरिवंश ने खड़गे का भाषण बीच में ही रोक दिया, ताकि कृषि मंत्री संबंधित विधेयक पर चर्चा कराये बिना मतदान करा सकें। हरिवंश ने कहा कि खड़गे का जोर भी इसी बात पर था कि सभी सदस्य कृषि कानूनों की वापसी का स्वागत ही कर रहे हैं, विरोध कोई भी नहीं कर रहा है क्योंकि इनकी वापसी किसानों के हित में है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बहस कराये जाने से इंकार कर दिया, क्योंकि सदन में व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी।

विपक्षी सदस्य ये नारे लगाते हुये "वैल" में चले गये थे कि दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक चले शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी जाये।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा अरावली प्रिन्टर्स, जयपुर रोड, अजमेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908